



Neutral Citation No. - 2026: AHC:4399-

आरक्षित:-17.12.2025

प्रदत्त किया गया:-08.01.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 3529/2024

चंद्रेश

....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : दिनेश कुमार पांडेय, मनु शर्मा, रणधीर जैन, संदीप कुमार केशरी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: आशीष पांडे, जी.ए.

चैंबर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-I

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रणधीर जैन और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।

2. विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (पाँक्सो अधिनियम), महाराजगंज द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 06.03.2024 के खिलाफ आपराधिक अपील दायर की गई है, जो मामला अपराध संख्या 89/2021, थाना- सिंदुरिया, जिला-महाराजगंज से उत्पन्न विशेष सत्र परीक्षण संख्या 544/2021 में अपीलकर्ता को दोषी ठहराते हुए और सजा सुनाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत सात साल की कैद और दो हजार रुपये जुर्माना और जुर्माने का भुगतान न करने अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर एक महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत जुर्माने का भुगतान न करने पर सात वर्ष की कैद और दो हजार रुपये का जुर्माना और एक महीने का कैद, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत एक वर्ष की कैद, बीस वर्ष की कैद और तीन हजार रुपये का जुर्माना और यौन अपराधों से बाल निवारण अधिनियम की धारा 6 के तहत जुर्माने का भुगतान न करने पर एक माह का कारावास और आजीवन कारावास और तीन हजार रुपये का जुर्माना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3 (2) (V) के तहत जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर एक महीने की कैद की सजा हो सकती है।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दिनांक 22.02.2021 को, त्रिभुवन गौर (अपीलकर्ता) के पुत्र चंद्रेश ने लगभग 18-1/2 वर्ष की सूचनादाता की बेटी को शादी करने के इरादे से बहकाया। उसकी बेटी 06.08.2021 को अपने घर लौट आई और बताया कि चंद्रेश ने उसे शादी करने के इरादे से बहकाया लेकिन उसने उससे शादी नहीं की और उसे अपने घर से निकाल दिया। वह शर्म की वजह से पहले पुलिस से संपर्क नहीं कर पा रही थी। आधार कार्ड के अनुसार उसकी बेटी की जन्म तिथि 01.01.2003 है।

4. पुलिस द्वारा मामले की जांच के बाद, अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 363, 366, 376, 506 पॉक्सो अधिनियम और एससी/एसटी अधिनियम की धारा -3 (2) (वी) के तहत आरोप तय किए। अपीलकर्ता ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की।

5. अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने पी.डब्ल्यू.-1, लीलावती देवी (सूचनादाता), पी.डब्ल्यू.-2, पीड़ित; पी.डब्ल्यू.-3, कांस्टेबल दुर्गेश कुमार गिरी; पी.डब्ल्यू.-4, डॉ. सतीश नारायण पांडेय, हेड मास्टर; पी.डब्ल्यू.-5, अरुण कुमार सिंह; पी.डब्ल्यू.-6, डॉ. अनुवेशिका श्रीवास्तव; पी.डब्ल्यू.-7, डॉ. सुनील कुमार पासवान और पी.डब्ल्यू.-8, अजय सिंह चौहान. का परीक्षण किया गया;

6. अपीलकर्ता से सीआरपीसी की धारा-313 के तहत पूछताछ की गई, जिसमें उसने कहा कि उसके खिलाफ एफआईआर गलत तरीके से दर्ज की गई थी और पक्षों के बीच पुरानी दुश्मनी के कारण झूठे सबूतों के आधार पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने चिकित्सा साक्ष्य से

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इनकार किया और वर्तमान मामले में झूठे आरोप लगाए। उन्होंने आगे कहा कि आईपीसी की धारा 354-ए, 504, 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत एक मामला संख्या 249/2017 उन पक्षों के बीच लंबित है जिसमें चंद्रेश (अपीलकर्ता) और उनके पिता त्रिभुवन आरोपी हैं। सूचनादाता लीलावती आदतन वादी है और अलग-अलग व्यक्तियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करके पैसे ऐंठती है। उपरोक्त वाद संख्या 249/2017 के अलावा, उसने आईपीसी की धारा 363, 366, 120-बी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत अपराध संख्या 42/2018 दर्ज किया है। समाज कल्याण विभाग से 8,25,000/- रुपये का मुआवजा प्राप्त करने के इरादे से पीड़िता और उसकी मां द्वारा पिछड़ी जाति से संबंधित अपीलकर्ता को झूठा फंसाने के लिए वर्तमान मामला अपराध संख्या 89/2021 भी दर्ज किया गया है। पी.डब्ल्यू.-1 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि घटना दिनांक 22.02.2021 समय, रात 11:00 बजे की है। घटना के समय, उसकी बेटी की उम्र लगभग 17 वर्ष थी और अपीलकर्ता ने उसे बेंगलूर से शादी के झूठे वादे पर बहकाया था। उसने उसे 06.08.2021 को रात 10:00 बजे शिकारपुर क्रॉसिंग पर वापस छोड़ दिया। उसकी बेटी (पी.डब्ल्यू.-2) ने उसे फोन किया और वह अपने बेटे के साथ शिकारपुर गई और अपनी बेटी को वापस अपने घर ले आई। उसने पी.डब्ल्यू.-1 को सूचित किया कि अपीलकर्ता की मां कौशल्या ने उसे फोन किया और फिर वह अपने घर गई, जहां उसका पति त्रिभुवन भी मौजूद था। अपीलकर्ता के भाई, विक्रम ने उसे अपीलकर्ता के साथ जाने का निर्देश दिया जो उससे शादी करेगा और उसे ठीक से रखेगा। विक्रम उसे और चंद्रेश को मोटर साइकिल पर ले गया और शिकारपुर क्रॉसिंग पर छोड़ दिया। अपीलकर्ता उसकी बेटी को बेंगलूर ले गया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसे अपनी पत्नी के रूप में रखा। उसकी बेटी गर्भवती हो गई। पी.डब्ल्यू.-2 से अपीलकर्ता, पी.डब्ल्यू.-1 के आचरण के बारे में जानने के बाद, वह पी.डब्ल्यू.-2 के साथ अपीलकर्ता के घर गई और उसके परिवार से कहा कि वह अपनी बेटी को अपने घर में अपनी बहू के रूप में रखे। चंद्रेश, उसकी मां, पिता और भाई ने उन्हें गाली दी और उनकी बेटी को यह कहते हुए धक्का दिया कि वह निचली जाति की है और वह उनके घर में नहीं रह सकती। उसकी बेटी गिर गई और उसका गर्भपात हो गया।

8. पी.डब्ल्यू.-2 ने अदालत के समक्ष अपने बयान में स्वीकार किया कि वह अपने दम पर अपना घर छोड़ गई और अपीलकर्ता के घर चली गई। अपीलकर्ता के भाई विक्रम के आश्वासन पर कि

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलकर्ता उसे ठीक से रखेगा और उससे शादी भी करेगा, अगर वह उसके साथ जाती है, तो वह अपीलकर्ता के साथ बेंगलोर चली गई। अपने बयान में उन्होंने स्वीकार किया है कि बेंगलुरु के रास्ते में कई पुलिसकर्मी और जनता का सामना करना पड़ा। उन्होंने सरकारी बस और ट्रेन के सार्वजनिक परिवहन में यात्रा की, लेकिन किसी भी समय उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाया या मदद के लिए नहीं रोया। उसने स्वीकार किया है कि अपीलकर्ता द्वारा उसे बेंगलोर से शिकारपुर क्रॉसिंग तक वापस छोड़ दिया गया था।

9. पी.डब्ल्यू.-3, पी.डब्ल्यू.-5 और पी.डब्ल्यू.-8 औपचारिक पुलिस गवाह हैं।

10. पी.डब्ल्यू.-4, स्कूल के हेडमास्टर यह साबित करने में सक्षम हैं कि पी.डब्ल्यू.-2 को उसके अभिभावक द्वारा सूचित जन्म तिथि के आधार पर कक्षा-VI में उसके स्कूल में प्रवेश दिया गया था। पी.डब्ल्यू.-4 के स्कूल में उसके प्रवेश के समय उसकी उम्र का कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया था, इसलिए, पी.डब्ल्यू.-4 द्वारा अपने बयान में 07.07.2003 के रूप में बताई गई पीड़िता की जन्म तिथि बिना किसी दस्तावेजी आधार के है।

11. पी.डब्ल्यू.-6 के बयान के अनुसार, पीड़िता 17.08.2021 को गर्भवती पाई गई थी और उसे पेट दर्द और रक्तस्राव की शिकायत थी।

12. पी.डब्ल्यू.-7, डॉ. सुनील कुमार पासवान ने साबित किया कि पीड़िता की उम्र लगभग 20 वर्ष थी। 23.08.2021 की ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार उनकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी।

13. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री और विचारण न्यायालय के फैसले के अवलोकन के बाद, हमारा विचार है कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को पारित करते समय रिकॉर्ड पर सबूतों पर ठीक से विचार नहीं किया है।

14. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियम, 2007 के नियम-12 के अनुसार, पहले उपस्थित स्कूल से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा -94 (2) के अनुसार, स्कूल से प्रमाण पत्र या मैट्रिक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी। इस मामले में पीड़िता मैट्रिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुई है।

15. हम पाते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने सी.एम.ओ. महाराजगंज द्वारा जारी पी.डब्ल्यू.-2 के आयु प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया है, जो 19.08.2021 को उसकी आयु लगभग 20 वर्ष साबित करता है। पी.डब्ल्यू.-1 के बयान और एफआईआर के अनुसार अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, वह 22.02.2021 को स्वेच्छा से अपने घर से भाग गई। पी.डब्ल्यू.-1 में पी.डब्ल्यू.-2 की आयु 18-1/2 वर्ष के रूप में उल्लेख किया गया है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में कानूनी सलाह पर उसने न्यायालय के समक्ष अपने बयान में पी.डब्ल्यू.-2 की आयु 17 वर्ष के रूप में उल्लेख किया।

16. स्पष्ट रूप से पी.डब्ल्यू.-2 मेजर थी और अपीलकर्ता के घर अपने घर से भाग गई थी और वहां से वह सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से गोरखपुर और वहां से बेंगलोर चली गई, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता के साथ जबरन विवाह के उद्देश्य से उसका जबरन अपहरण किया गया था। वह अपीलकर्ता के साथ अपने निवास स्थान पर लौटने से पहले 6 महीने तक अपीलकर्ता के साथ अन्य घरों से भरे इलाके में रही। इसलिए, धारा 363, 366 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि कानून के अनुसार पूरी तरह से अनुचित है।

17. यदि पीड़ित बालिग थी, तो पाँक्सो अधिनियम की धारा-6 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि भी अनुचित है। आईपीसी की धारा-376 के तहत दोषसिद्धि भी उचित नहीं है क्योंकि पीड़ित बड़ी उम्र की थी और अपीलकर्ता के साथ छह साल तक सहमति से संबंध था।

18. अपने दम पर अपना घर छोड़ने और 6 महीने तक अपीलकर्ता के साथ रहने, उसके साथ शारीरिक संबंध रखने, इस अवधि के दौरान कभी भी अपनी मां या उसके परिवार के किसी को भी कोई कॉल नहीं करना और 06.08.2021 को अपीलकर्ता द्वारा शिकारपुर क्रॉसिंग पर छोड़ने के बाद ही अपनी मां को फोन करना यह साबित करता है कि पी.डब्ल्यू.-2 ने अपीलकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। गर्भवती हो गई। इसके बाद, उन्हें सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों से, अपीलकर्ता और पीडब्ल्यू.-2 बेंगलोर से लौट आए और दोनों अपने रास्ते अलग हो गए। जबकि, पीडब्ल्यू.-2, फोन पर फोन करने के बाद उसकी मां के पास गई, अपीलकर्ता अपने घर चला गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह आरोप लगाया गया है कि बाद में पी.डब्ल्यू.-1 और पी.डब्ल्यू.-2 अपीलकर्ता के घर गए जहां उनके और परिवार के सदस्यों ने पी.डब्ल्यू.-2 को उसकी जाति के आधार पर अपने घर में रहने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अपीलकर्ता के परिवार के सदस्यों ने उसे धक्का दिया, वह गिर गई और गर्भपात हो गया।

19. एससी/एसटी अधिनियम की धारा-3(2)(वी) के तहत सजा स्वतंत्र प्रावधान नहीं है और यह केवल तभी लागू होती है जब आरोपी को आईपीसी के प्रावधान के तहत 10 साल या उससे अधिक की कैद की सजा दी जाती है, इसलिए एससी/एसटी अधिनियम की धारा-3(2)(वी) के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि भी टिकाऊ नहीं है और एतद्वारा अपास्त की जाती है।

20. आईपीसी की धारा 323 के तहत दोषसिद्धि और सजा भी अनुचित है क्योंकि पीडब्ल्यू-2 को धक्का देने का कार्य अपीलकर्ता नहीं बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को अधिरोपित किया गया है।

21. अलग होने से पहले, हम पाते हैं कि यह मामला पश्चिमी विचारों और लिव-इन की अवधारणा के प्रभाव में विवाह के अनुष्ठान के बिना एक साथ रहने वाले युवाओं की बढ़ती प्रवृत्ति का एक उदाहरण है। इस तरह के रिश्ते विफल होने के बाद, एफआईआर दर्ज की जाती है और कानून महिलाओं के पक्ष में होते हैं, लड़के/पुरुषों को उन कानूनों के आधार पर दोषी ठहराया जाता है जो तब बनाए गए थे जब लिव-इन की अवधारणा कहीं भी अस्तित्व में नहीं थी।

22. उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और एतद्वारा अपास्त की जाती है।

23. अपीलकर्ता जेल में है, उसे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं होने पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

24. आपराधिक अपील की अनुमति है।

25. कार्यालय को विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड को वापस करने और दो सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय को इस फैसले को सूचित करने का निर्देश दिया जाता है।

जनवरी 8, 2026

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभिषेक

(न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा-1) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

Translated Version. Not for Legal Use

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।